Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to undertake fresh Socio-Economic Caste Census.

श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) :

1. केन्द्र सरकार के द्वारा देशभर में गरीबों के उत्थान के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम एवं योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, वृद्धा एवं विधवा पेंशन, चिकित्सा अनुदान, राशन कार्ड आदि कई योजनाओं का लाभ वर्ष 2011 में संपन्न सामाजिक-आर्थिक-जातिगत जनगणना (सेक) को आधार मानकर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को प्रदान किया जाता है, परंतु वर्ष 2011 में संपन्न उक्त जनगणना की सूची में व्यापक विसंगतियां भी पायी गयी हैं, क्योंकि उक्त सूची में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्ण जाति के अधिकांश लोगों का नाम दर्ज नहीं होने के कारण उपरोक्त कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिकांश गरीबों को नहीं मिल रहा है। साथ ही उक्त जनगणना के सात (7) वर्ष पश्चात अनेक नये परिवार बीपीएल श्रेणी के पात्र हैं, उन्हें भी उक्त योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है।

2. हमारे संसदीय क्षेत्र के लगभग सभी प्रखंडों में अनेक ऐसे सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्ण जाति अथवा बीपीएल श्रेणी की अहर्ता रखने वाले लोग हैं, जिनके पास अपना जमीन है और कच्चा मकान है, लेकिन वर्ष 2011 की SECC सूची में नाम दर्ज नहीं होने के कारण उन्हें प्रधानमंत्री

आवास योजना अथवा अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है जो वास्तव में अत्यंत गरीब और जरूरतमंद है।

अतएव केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि, जब तक सामाजिक-आर्थिक-जातिगत सर्वेक्षण पुन: नहीं हो जाता है तब तक प्रखंड स्तर पर ही विशेष सर्वेक्षण कराकर सामान्य, पिछड़ा, दलित आदिवासी आदि वर्ग के सभी जातियों के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े और अत्यंत गरीब परिवारों को चिन्हित किया जाए तथा उपरोक्त सभी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाए ताकि सबका साथ, सबका विकास का सरकार के संकल्प को पूरा किया जा सके।